# ऑल यूनियन्स एंड एसोसिएशन्स ऑफ बीएसएनएल (AUAB)
# मध्यप्रदेश परिमंडल, भोपाल

.....

## हड़ताल के लिए हम बाध्य क्यों ?

- DoT ने अब कहा 0% फिटमेंट के साथ भी 3rd पे रिवीजन संभव नहीं।
- टाईम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है .....
  - सरकार BSNL को बंद करना चाहती है / रणनीतिक साझेदार को बेचना चाहती है।
  - सरकार BSNL के बडी संख्या में शेयर बेचकर स्ट्रेटेजिक पार्टनर की खोज में है।
- सीएमडी फरवरी 2019 की सैलरी कुछ समय तक रोकने का अनुरोध कर रहे है।
- BSNL को बैंकों से लोन लेने की अनुमति नहीं दी जा रही है।
- रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 से 58 करने की सुगबुगाहट भी होती रही है। VRS की योजना बना कर भय निर्मित किया जा रहा है।
- जीपीएफ, बैंक, सोसायटी, एलआईसी की किश्तें वेतन से कटौत्रा करने के बावजूद संबंधित संस्थाओं को प्रेषित नहीं की जा रही है।
- रिलायंस जिओ को सरकार का पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। भारतीय रेल ने बीएसएनएल की बजाय रिलायंस जियो के कनेक्शन ले लिए हैं।
- BSNL को अपनी रिक्त जमीन व भवनों का व्यावसायिक उपयोग करने में बाधाएं निर्मित की जा रही है। जबकि इससे BSNL को करोड़ों का राजस्व प्राप्त हो सकता है।
- BSNL की असेट्स (संपत्ति) BSNL को स्थानांतरित नही की जा रही है।
- BSNL की क्षीण वित्तीय स्थिति के बावजूद अनावश्यक रुप से टॉवर्स के मेंटेनेंस का कार्य अनाप-शनाप दरों पर आउटसोर्स कर करोड़ो रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं।
- BSNL को 4G स्पेक्ट्रम के आवंटन में बाधाएं निर्मित की जा रही है।
- हमारे युवा साथियों के II PRC के शेष मुद्दे, SAB, E2/E3 आदि आश्वासन के बावजूद लंबित है।
- पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन के भुगतान में सरकार के नियमों का लाभ BSNL को नहीं मिल रहा है।
- ऐसे में, हमारे संघर्ष के बूते ही हम BSNL की जीवंतता सुनिश्चित कर सकते हैं।

### अब हमारे सामने एक ही रास्ता है -

**हडताल और सिर्फ हडताल।** पिछली बार हडताल क्यों नहीं हुई ... भूल जाइए। अब बहोत विकट, विकराल और भयावह स्थिति निर्मित हुई है। हमने BSNL को सरकारी हमलों से 01.10.2000 से अब तक सुरक्षित रखा है। हम आज भी BSNL को ध्वस्त और धराशायी करने के सरकार के इरादों को परास्त करने में सक्षम हैं। लडाई अस्तित्व की है... अबकी बार, आर या पार... संघर्ष करेंगे जोरदार।

**तो आइए .... सब मिलकर, एक साथ संघर्ष का शंखनाद करें – BSNL को बंद करने की चर्चा छेड कर सरकार ने हमें ललकारा हैं, हम इसका करारा जवाब देंगे।**

**18.2.2019 से तीन दिन ऐतिहासिक हड़ताल कर हम हमारे अधिकारों को प्राप्त करेंगे।**